

प्रेषक,

किशन नाथ,  
अपर सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

श्रम आयुक्त,  
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

श्रम एवं सेवायोजन अनुभाग

देहरादून दिनांक: 31 मई, 2012

विषय:- चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के लेखानुदान में प्राविधानित धनराशि की अवचनबद्ध मदों में स्वीकृति प्रदान किए जाने विषयक।

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रमुख सचिव, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या:- 193/XX VII(1)/2012, दि. 30 मार्च, 2012 के क्रम में एवं वित्तीय वर्ष 2012-13 के लेखानुदान की वित्तीय स्वीकृतियाँ अवचनबद्ध मदों में श्रम विभाग के अनुदान संख्या-16 में संलग्न-विवरणानुसार आयोजनेतर पक्ष में रु. 16,88,000.00 (रु० सोलह लाख अठ्ठासी हजार मात्र) की धनराशि को संलग्न अलोटमेंट आई०डी०-SI205161150, SI205161151, SI205161152, SI205161153, SI205161154, SI205161155 एवं SI205161160 के अनुसार आपके निर्वतन पर रखते हुये व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ एवं शर्तों के अधीन आपके निर्वतन पर रखी जा रही है, कि उक्त मदों में आवंटित धनराशि का व्यय सीमित रखा जाये। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है, कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। जहाँ व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा। व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है, मितव्ययिता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

3- इस संबंध में यह ध्यान दिया जायेगा कि यदि किसी मुद्रण/लिपिकीय त्रुटि से किसी मद में माँग से अधिक धनराशि बजट प्राविधान प्रदर्शित हो रहा हो तो वहाँ वास्तविक आवश्यकता के आधार पर ही कार्यवाही की जायेगी।

4- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के अनुदान संख्या-16, 30 एवं 31 के मुख्य लेखाशीर्षक 2230-श्रम तथा रोजगार की सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा। यह आवंटन ~~श्रम~~ विभाग के अधीन समस्त कार्यालयों के लिए किया जा रहा है।

5- प्रायः यह देखा गया है कि धनराशि विभागाध्यक्ष के निर्वतन पर रखने के उपरान्त भी विभागाध्यक्ष द्वारा वह धनराशि आहरण वितरण अधिकारियों के निर्वतन पर नहीं रखी जाती है, जिससे क्षेत्रीय स्तर पर व्यय हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं होती है। अतः वर्तमान में स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरण-वितरण अधिकारी को तत्काल अवमुक्त कर दी जाए और फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो सके। धनराशि का उपयोग दि. 31 मार्च, 2013 तक करते हुये प्रत्येक माह का बी.एम.-13 शासन को उपलब्ध कराया जाएगा।



6- वित्त विभाग के उपरिलिखित शासनादेश दिनांक 30 मार्च, 2012 द्वारा बजट आहरण एवं आवंटन के सम्बन्ध में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

7- उक्त आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या:-193/XXVII(1)/2012 दिनांक: 30 मार्च, 2012 में प्राप्त निर्देशों के क्रम में जारी किए जा रहे हैं।

संलग्न : यथोपरि।

भवदीय

(किशन नाथ)  
अपर सचिव

संख्या:- 950 (1)/VIII/12-25(श्रम)/2012, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. एन.आई.सी., उत्तराखण्ड, सचिवालय परिसर।
2. वित्त अनुभाग-5।
3. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अहमद अली

(अहमद अली)  
अनु सचिव।

०